



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्रकाशित हो

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 132]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2009/चैत्र 9, 1931

No. 132]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2009/CHAITRA 9, 1931

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2009

सं. 167 (आर ई-2008)/2004—2009

फा. सं. 01/94/180/982/एम 09/पी सी-4.—विदेश व्यापार नीति, 2004—2009 के पैराग्राफ 2.4 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेश व्यापार महानिदेशक, एतद्वारा, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) (आर ई-2008) में, निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

1. पैराग्राफ 2.20 के अंत में, “अध्याय 3 के तहत डीईपीबी/मुक्त रूप से हस्तांतरणीय प्रोत्साहन योजना के लिए बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन” से संबंधित नीचे यथा उल्लिखित एक नया पैराग्राफ 2.20क जोड़ा जाएगा :

अध्याय 3 के तहत डीईपीबी/मुक्त रूप से हस्तांतरणीय प्रोत्साहन योजना के लिए बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन	2.20क	बैंक प्राप्ति प्रमाण-पत्र (बीआरसी) के बगैर विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत डीईपीबी योजना/मुक्त रूप से हस्तांतरणीय योजना के तहत स्क्रिप (स्क्रिप्स) के लिए आवेदन प्रस्तुत करते समय, आवेदक क्रमशः परिशिष्ट 25ग या परिशिष्ट 25घ के अनुसार क्षेत्रीय प्राधिकारी के साथ बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता (सीमा-शुल्क परिपत्र सं. 58/2004 अनुसार) को प्रस्तुत करेगा।
--	-------	---

2. इस सार्वजनिक सूचना के साथ यथासंलग्नित “अध्याय 3 के तहत डीईपीबी/मुक्त रूप से हस्तांतरणीय योजना के लिए बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का निष्पादन” से संबंधित दो नए परिशिष्ट अर्थात् परिशिष्ट 25ग और परिशिष्ट 25घ को प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 (परिशिष्ट और आयात-निर्यात प्रपत्र) में जोड़ा जाता है।

3. सार्वजनिक सूचना सं० 151 दिनांक 26.2.2009 द्वारा अधिसूचित पैराग्राफ 3.23.13 धारा 1 के अंतिम वाक्य को निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा :

“यदि कोई दावा लंबित नहीं है और स्क्रिप जारी किए जाने की तिथि से 12 महीने की समाप्ति के तुरंत बाद कोई नकद राशि जमा नहीं की गई है, तो क्षेत्रीय प्राधिकारी आवश्यक कार्रवाई शुरू करेगा। यदि स्क्रिप धारक, उपरोक्त 12 महीने की समयावधि के समाप्त होने के 60 दिनों के अंदर राशि की अदायगी नहीं करता है, तो स्क्रिप धारक को उपरोक्त राशि को ड्यूटी क्रेडिट के लिए जिसके लिए बीआरसी या दस्तावेजी प्रमाण (विदेश व्यापार नीति या इसके तहत निर्धारित प्रक्रिया के तहत यथा अपेक्षित निर्यात आय की प्राप्ति का प्रमाण) के साथ स्क्रिप जारी करने की तिथि से 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा। यदि स्क्रिप धारक अप्रयुक्त/आंशिक रूप से अप्रयुक्त ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप को वापस कर देता है तब अप्रयुक्त/आंशिक रूप से अप्रयुक्त क्रेडिट चुकायी जाने वाली राशि से निकाली जाएगी।

4. सार्वजनिक सूचना सं. 151 दिनांक 26.2.2009 द्वारा यथा संशोधित पैराग्राफ 4.45 को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :-

“क्षेत्रीय प्राधिकारी ऐसे सभी मामलों का निरीक्षण करेगा जिनमें स्क्रिप (स्क्रिपों) को बगैर बैंक प्राप्ति प्रमाण-पत्र (बीआरसी) के जारी कर दिया गया है और यह सुनिश्चित करेगा कि स्क्रिप जारी करने की तिथि से 12 महीने के अंदर बी आर सी को प्रस्तुत कर देगा। यदि कोई आरबीआई समयावधि विस्तार प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो क्षेत्रीय प्राधिकारी उसकी वसूली के लिए कार्रवाई शुरू करेगा। ऐसे मामलों में, डीईपीबी धारक (मूल आवेदक) नकद या वैध डीईपीबी/अनुमत शुल्क मुक्त क्रेडिट के बराबर राशि के लिए लंबित डीईपीबी दावों के समायोजन के डेबिट द्वारा जमा करवाएगा। यदि मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त राशि कम है तब चुकाई जाने वाली राशि आनुपातिक रूप से कम कर दी जाएगी। तथापि, यदि डीईपीबी धारक स्क्रिप जारी होने की तिथि से 12 महीने की समयावधि समाप्त होने के 60 दिनों के अंदर राशि को नहीं चुकाता है, तो उसे उपरोक्त राशि को ड्यूटी क्रेडिट के लिए स्क्रिप (स्क्रिपों) जारी किए जाने की तिथि से 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित उक्त राशि को चुकाना अपेक्षित होगा जिसके लिए बीआरसी या दस्तावेजी प्रमाण (विदेश व्यापार नीति या इसके तहत निर्धारित प्रक्रिया के तहत यथा अपेक्षित निर्यात आय की प्राप्ति का प्रमाण) डीईपीबी धारक द्वारा प्रस्तुत नहीं किए जा सके। यदि वह अप्रयुक्त/ आंशिक रूप से अप्रयुक्त ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप को वापस कर देता है, तो अप्रयुक्त/आंशिक रूप से अप्रयुक्त क्रेडिट चुकाई जाने वाली राशि से काट लिया जाएगा।”

नकद अदायगी के मामले में, इसे उपरोक्त पैराग्राफ 4.29 के अनुसार सीमाशुल्क के लेखा शीर्ष में जमा करवाया जाएगा।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

परिशिष्ट 25 ग**अध्याय 3 में डीईपीबी स्कीम और मुक्त हस्तांतरणीय प्रोत्साहन स्कीमों हेतु
बैंक गारंटी प्रपत्र**

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति
महानिदेशक, विदेश व्यापार
के जरिए कार्य कर रहे हैं

महानिदेशक, विदेश व्यापार जिसमें (संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार/उप-महानिदेशक, विदेश व्यापार शामिल हैं या संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार/उप-महानिदेशक, विदेश व्यापार की ऊचूटी करने के लिए फिलहाल प्राधिकृत किया गया अन्य कोई प्राधिकारी) वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के जरिए भारत के राष्ट्रपति जिसे इसमें आगे सरकार कहा गया है

को समय-समय पर यथा

संशोधित विदेश व्यापार नीति 2004-2009 के तहत सरकार द्वारा अधिसूचित ———

स्कीम (वास्तविक विशिष्ट स्कीम का नाम भरें) ।

आयातक - निर्यातक (आयातक/निर्यातक का पूरा विस्तृत नाम, पूरा पता और आई ई सी सं०) (इसके बाद इसे 'पार्टी' कहा जाएगा जिस अभिव्यक्ति में उसके वारिस, उत्तराधिकारी, प्रशासक और समनुदेशिनी को शामिल माना जाएगा, यदि यह फर्म पूर्ण स्वामित्व वाली फर्म है/संयुक्ततः और पृथकतः इनके सभी हिस्सेदार, कानूनी वारिस/उत्तराधिकारी/प्रशासक और समनुदेशिनी और जहाँ उक्त फर्म के कार्यों का नियंत्रण निगमित निकाय द्वारा किया जा रहा है, या नहीं किया जा रहा है, यदि यह साझेदारी फर्म/व्यापार में उत्तराधिकारी और समनुदेशिनी है, यदि फर्म लिमिटेड कम्पनी है) स्कीम की शर्तों को पूरा करने पर पार्टी स्क्रिप (इसके बाद स्कीम के तहत अनुमत माल के आयात के लिए स्क्रिप कहा जाएगा) के लिए आवेदन करने को इच्छुक हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ बैंक गारंटी प्रस्तुत करना निर्दिष्ट करती है यदि पार्टी स्क्रिप के लिए बैंक वसूली प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज के बिना जो निर्यात आय की प्राप्ति (स्कीम की शर्तों के अनुसार) का प्रमाण देते हुए, आवेदन करती है । हम

..... (बैंक का नाम, पूरा पता एवं अन्य विवरण लिखें) (इसके बाद बैंक कहा जाएगा) पार्टी के अनुरोध पर एतद्वारा बिना शर्त और अपरिवर्तनीय रूप से उक्त पार्टी द्वारा बैंक वसूली प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेज जो स्क्रिप में पृष्ठांकित समयावधि के भीतर निर्यात आय (स्कीम की शर्तों के अनुसार) की वसूली का प्रमाण देते हैं; प्रस्तुत करने में असफल होने के कारण सरकार को या द्वारा किसी नुकसान या क्षति के भदे रुपये से कम रकम की अदायगी करने का वचन देते हैं ।

2. हम (बैंक का नाम लिखें) एतद्वारा इस गारंटी के तहत देय राशि का बिना किसी आपत्ति या विरोध के भुगतान करने का वचन देते हैं ; जो सरकार द्वारा केवल यह कहने पर कर दिया जायेगा कि पार्टी द्वारा उक्त स्कीम की शर्तों का उल्लंघन करने के कारण सरकार को हुई हानि या नुकसान होने पर दावे की देय हो गई है । जहां तक बैंक द्वारा और बैंक को देय राशि का सम्बंध है, बैंक से की गई ऐसी कोई भी मांग अंतिम होगी ।

3. हम पार्टी द्वारा किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के सम्मुख तत्संबंधी दायर किसी मुकदमे या कार्रवाही के माध्यम से उठाए गए किसी विवाद के होते हुए भी और इसके अधीन हमारी निरपेक्ष एवं सुस्पष्ट देयता के तहत मांगी गई किसी धनराशि को सरकार को भुगतान करने का वचन देते हैं ।

4. हम (बैंक के नाम का उल्लेख करें) आगे सहमत हैं कि इसमें निहित गारंटी पूर्णतया लागू रहेगी और उक्त स्क्रिप के निष्पादन के लिए जो समय लिया जायेगा उस अवधि के दौरान प्रभावी रहेगी और यह कि तब तक लागू रहेगी जब तक कि उस स्क्रिप के तहत अथवा उसके जरिए पार्टी द्वारा सभी दायित्वों को सरकार की संतुष्टि के अनुसार पूरा कर दिया जाता है या जब तक संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार/उप महानिदेशक, विदेश व्यापार या संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार/उप महानिदेशक विदेश व्यापार वाणिज्य मंत्रालय, नई दिल्ली के कार्यों के निष्पादन हेतु प्राधिकृत किसी क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा यह प्रमाणित नहीं कर दिया जाता कि पार्टी द्वारा उक्त स्क्रिप के निबंधन एवं शर्तों का पूर्णरूपेण तथा समुचित ढंग से पालन किया गया है और तदनुसार यह गारंटी निष्पादित की गई है । तथापि परन्तु, जब तक हमारे पास दिनांक ————— को या इससे पूर्व इस गारंटी के अधीन लिखित रूप में मांग या दावा प्रस्तुत नहीं किया जाता है । हम उसके बाद इस गारंटी के अधीन सभी देयताओं से विमुक्त हो जायेंगे ।

5. हम ————— (बैंक के नाम का उल्लेख करें) आगे सरकार से सहमत हैं कि हम से सहमति लिए बिना और इसके तहत हमारे निर्यात दायित्वों को किसी भी रूप में प्रभावित किए बिना सरकार को (i) समय-समय पर उक्त स्क्रिप के किसी निबंधन एवं शर्त को बदलने तथा उक्त स्कीम में फेरबदल करने या (ii) समय-समय पर उक्त पार्टी द्वारा निष्पादन के समय में विस्तार अथवा किसी समय के लिए स्थगित करने अथवा (iii) उक्त पार्टी के विरुद्ध सरकार द्वारा समय-समय पर किसी शक्ति का प्रयोग करने और उक्त स्क्रिप के संबंध में किसी शर्त या निबंधन को स्थगित या लागू करने की पूरी स्वतंत्रता होगी, और किसी ऐसे परिवर्तन, या सरकार द्वारा उक्त स्क्रिप धारक को किसी स्थगन अधिनियम या चूक से मुक्त करने के लिए दिये जा रहे विस्तार या उक्त पार्टी के प्रति सरकार के किसी अनुग्रह या इस उपबंध के न होन पर भी जमानत से संबंधित कानून के अधीन हमारी ऐसी विमुक्तियों को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले या कार्य, किसी भी कारण से हम अपनी देयता से विमुक्त नहीं होंगे।

कि यह एक सतत बैंक गारन्टी होगी और पार्टी अथवा बैंक की व्यवस्था में किसी भी परिवर्तन द्वारा विमुक्त नहीं होगी।

यह कि गारंटीकर्ता सरकार की लिखित पूर्व सहमति के बिना गारंटी वापिस नहीं लेगा।

" तारीख.....दिन..... वर्ष "

कृते..... (बैंक का नाम लिखें)

टिप्पणी : 1. बैंक गारन्टी/विधिक वचनबद्धता प्रक्रिया पुस्तक खण्ड 1 के पैराग्राफ 2.20 के अनुसार होगी।

2. * अध्याय 4 के तहत डीईपीबी/विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत विशिष्ट हस्तांतरणीय प्रोत्साहन स्कीम।

3. **बैंक गारन्टी निर्यात (अनुमत निर्यात आदेश तिथि) की तारीख से 24 माह की अवधि की समाप्ति तक वैध होगी। डीईपीबी स्कीम/प्रोत्साहन स्कीम के तहत एक आवेदन के मद्दे अनेक एस/बी प्रस्तुत करने के मामले में, 24 माह की अवधि, नवीनतम एस/बी की अनुमत निर्यात तिथि से होगी।

1250 GI/09-2

परिशिष्ट 25घअध्याय 3 में डीईपीबी स्कीम और मुक्त हस्तांतरणीय प्रोत्साहन स्कीमों हेतु विधिक
करार/वचनबद्धता का प्रपत्र

सेवा में,

भारत के राष्ट्रपति

महानिदेशक, विदेश व्यापार (संयुक्त महानदेशक, विदेश व्यापार/उप
महानिदेशक, विदेश व्यापार को भी इस अभिव्यक्ति में शामिल माना जाएगा) वाणिज्य
मंत्रालय, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110011

इस करार का विलेख माह..... वर्ष.....
को निष्पादित किया गया ।

करार का यह विलेख दो पक्षकारों नीचे दिए गए अनुदेशों
के अनुसार (आयातक/निर्यातक का पूरा विस्तृत नाम और पूरा पता) जिसे इसमें आगे
"पार्टी" कहा गया है जिसके अन्तर्गत उसके वारिस, प्राधिकारी, प्रशासक और
समनुदेशिती, यदि यह फर्म पूर्ण स्वामित्व वाली फर्म है/संयुक्ततः और पृथकततः इनके
सभी हिस्सेदार, कानूनी वारिस/उत्तराधिकारी/प्रशासक और समनुदेशिती और जहाँ उक्त
फर्म के कार्यों का नियन्त्रण निगमित निकाय द्वारा किया जा रहा है, या नहीं किया जा
रहा है, यदि यह साझेदारी फर्म/व्यापार में उत्तराधिकारी और समनुदेशिती है, यदि फर्म
लिमिटेड कम्पनी है, को भी पार्टी समझे जाएंगे ।

और

भारत के राष्ट्रपति (जिन्हें आगे सरकार कहा गया है और जिसके अन्तर्गत कार्यालय
और समनुदेशन में उसके उत्तराधिकारी) ।

जबकि स्कीम की शर्तों को पूरा करने पर पार्टी स्क्रिप (इसके बाद स्कीम के तहत अनुमति माल के आयात के लिए स्क्रिप कहा जाएगा) के लिए आवेदन करने को इच्छुक हैं, जो अन्य बातों के साथ-साथ एक विधिक वचनबद्धता (इसके बाद से 'एल यू टी' कहा जाएगा) प्रस्तुत करना निर्दिष्ट करती है यदि पार्टी स्क्रिप पर पृष्ठांकित समयावधि के भीतर निर्यात आय (निर्यात का पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य जिसके आधार पर स्कीम के तहत ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप की अनुमति दी जाएगी) एक दायित्व सहित प्राप्त करने के लिए समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2004-2009 के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिसूचित.....स्कीम (वास्तविक विशिष्ट स्कीम भरें) (इसके बाद से 'स्कीम' कहा जाएगा) के अधीन यथा अपेक्षित निर्यात आय की प्राप्ति का साक्ष्य देने वाले बैंक प्राप्ति प्रमाण पत्र अथवा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना स्क्रिप के लिए आवेदन करती है।

और जबकि सरकार पार्टी को, आवेदन किए गए पूरे मूल्य के लिए या इससे कम मूल्य के लिए जैसा ठीक समझा जाए और स्कीम की शर्तों के अनुसार स्क्रिप की स्वीकृति दे सकती है।

और जबकि, स्क्रिप की किसी एक शर्त, जो उपरोक्त के अनुसार जारी की गई हो, यह है कि पार्टी को इसके बाद आने वाली शर्तों पर सरकार के साथ करार/वचनबद्धता करनी होगी।

और जबकि उक्त स्कीम की किसी शर्त के पार्टी द्वारा उल्लंघन के कारण सरकार द्वारा उठाई गई हानि अथवा निर्यात आय की वसूली न होने के मामले में दावित राशि सरकार द्वारा माँगे जाने पर बिना किसी आपत्ति अथवा विरोध के, इस करार के तहत कम से कमरुपए की राशि बकाया है जिसे सरकार को बिना शर्त अपरिवर्तनीय रूप से पार्टी को भुगतान करना होगा।

और जबकि, स्कीम के तहत अनुमतत ड्यूटी क्रेडिट के आधार पर निर्यात के मद्दे निर्यात आया की वसूली के दायित्व के आधार पर, उपरोक्त के अनुसार सरकार से जारी स्क्रिप की प्रत्याशा में पार्टी को एक विधिक करार प्रस्तुत करना होगा।

और जबकि, पार्टी स्क्रिप में दर्शाए गए पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के बराबर अथवा जारी की गई स्क्रिप के तहत आवश्यक समयावधि के भीतर स्क्रिप में सरकार द्वारा यथापृष्ठांकित निर्यात आय वसूली पर सहमत है।

और जबकि पार्टी ने करार किया है कि :-

- क)स्कीम (स्कीम का नाम लिखें) की सभी शर्तें पूर्ण करेगी जिसके अन्तर्गत स्क्रिप जारी की जा सकती है;
- ख) वह जारी किए जाने वाले स्क्रिप की सभी शर्तें पूरी करेगी ।
- ग) वे स्कीम से संबंधित संगत सीमा शुल्क अधिसूचना के अन्तर्गत लगाई गई शर्तों सहित सभी शर्तें पूर्ण करेगी जिसके अधीन सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा माल की निकासी की जाएगी ।
- घ) प्रत्येक स्क्रिप के जारी होने की तारीख से प्रत्येक तीन महीने में, संबंधित क्षेत्रीय प्राधिकारी को, पोत लदान के अनुसार मूल रूप से “निर्यात आय वसूली का विवरण” भेजेगा ।
- ङ.) जिस पर स्क्रिप जारी होनी है उस पर पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य हेतु मूल रूप में राष्ट्रीय/अनुसूचित बैंक से बैंक प्रमाण पत्र अथवा किए गए निर्यात आय की वसूली के लिए साक्ष्य के तौर पर क्षेत्रीय प्राधिकारी द्वारा माँगे गए दूसरे अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करेगी ।
- च) कि उपरोक्त दायित्वों/शर्तों को पूरा न कर पाने के मामले में, वह जारी ड्यूटी क्रेडिट के बराबर की राशि का तत्काल भुगतान करेगा । यदि स्क्रिप जारी होने की तारीख से 12 महीने की समयावधि के समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर पार्टी भुगतान नहीं करती तो, पार्टी को, विदेश व्यापार नीति अथवा उसके तहत लागू प्रक्रिया के अनुसार यदि पार्टी, ड्यूटी क्रेडिट के लिए बीआरसी अथवा दस्तावेजी साक्ष्य (निर्यात आय की वसूली का साक्ष्य) प्रस्तुत नहीं कर सकती तो उस ड्यूटी क्रेडिट पर स्क्रिप जारी होने की तारीख से प्रति वर्ष 15 प्रतिशत ब्याज सहित उक्त रकम का भुगतान करना होगा । पार्टी के अप्रयुक्त/अंशतः अप्रयुक्त ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप वापस करने पर अप्रयुक्त/अंशतः अप्रयुक्त क्रेडिट को भुगतान की जाने वाली राशि से घटा दिया जाएगा।
- छ) सरकार समय-समय पर स्कीम का संशोधन करेगी ।

अब करार की शर्तें निम्नलिखित हैं :-

उपरोक्त के अनुसार सरकार द्वारा उक्त स्क्रिप की मंजूरी को देखते हुए, पार्टी एतद्वारा यह घोषणा करती है और सहमत है कि वह :

1. यह कि पार्टी पूर्वोक्त स्कीम के अन्तर्गत सरकार द्वारा अधिसूचित सभी दायित्वों और आयात के लिए जारी स्क्रिप में उल्लिखित शर्तों और उपरोक्त सभी शर्तों का अनुपालन करेगी ।
2. यदि पार्टी स्क्रिप में अनुबन्ध शर्तों सहित स्कीम के तहत निर्यात आय को पूर्णतः या अंशतः पूरा करने में असफल रहती है अथवा विदेश व्यापार (विकास व विनियमन) अधिनियम 1992, या उसके अधीन दिए गए यथा संशोधित आदेशों या उसके अधीन बनाए गए कानूनों के अन्तर्गत अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने में असफल रहती है तो वह सरकार द्वारा मांगी गई पूरी रकम या उसके किसी भाग का बिना किसी आपत्ति अथवा विरोध के सरकार को भुगतान करेगी ।
3. यह कि किसी अधिकार के होते हुए भी और पार्टी द्वारा किसी भी रूप में उठाए गए विवाद के होते हुए भी पार्टी के लिए सरकार की लिखित मांग अन्तिम और स्वीकार्य होगी ।
4. यह कि यह करार जारी रहेगा और पार्टी के संविधान में परिवर्तन हो जाने के बावजूद यह निरस्त नहीं होगा ।
5. यह कि पार्टी साथ ही साथ सरकार को नुकसान की प्रतिपूर्ति करने के लिए वचनबद्ध है जो ड्यूटी क्रेडिट होगी । सरकार का निर्णय अन्तिम और पार्टी के लिए स्वीकार्य होगा ।
6. यह कि यह करार पार्टी द्वारा लोकहित में किया गया है ।
7. यह कि इस करार के तहत सरकार द्वारा मांगी गई रकम का भुगतान करने से किसी अन्य कार्रवाई के लिए पार्टी के दायित्व पर, जिसमें आयातित सामग्री की जब्ती के लिए विधिक कार्रवाइयों को प्रारम्भ करना और आगे स्क्रिप/प्राधिकार पत्र देने से इंकार करना शामिल हैं, पर प्रभाव नहीं पड़ेगा और विदेश व्यापार (विकास व विनियमन) अधिनियम 1992 के प्रावधानों और उसके अधीन बनाये गए आदेशों, जिन्हें सरकार निश्चित करे, के तहत सभी दायित्वों, जुर्मानों और परिणामों पर भी प्रभाव नहीं पड़ेगा ।
8. यह कि यह करार तब तक प्रभावी रहेगा जब तक पार्टी के सभी दायित्व

उपर्युक्तानुसार सरकार की पूर्ण और अन्तिम रूप से संतुष्टि के अनुसार पूरा नहीं कर दिया जाता और जब तक ऐसी संतुष्टि की सूचना पार्टी को नहीं दे दी जाती ।

9. कि, स्क्रिप के जारी होने की तारीख से 12 महीने की समयावधि के भीतर निर्यात आय की वसूली के प्रमाण के रूप में बैंक वसूली प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के उपरोक्त दायित्व को पूरा करने में सफ न होने पर पार्टी बिना शर्त, और अपरिवर्तनीय रूप से, जारी किए गए ड्यूटी क्रेडिट के बराबर राशि का तत्काल भुगतान करेगी । यदि स्क्रिप जारी होने की तारीख से 12 महीने की समयावधि के समाप्त होने के 60 दिनों के भीतर पार्टी भुगतान नहीं करती तो, पार्टी को, विदेश व्यापार नीति अथवा उसके तहत लागू प्रक्रिया के अनुसार यदि पार्टी, ड्यूटी क्रेडिट के लिए बीआरसी अथवा दस्तावेजी साक्ष्य (निर्यात आय की वसूली का साक्ष्य) प्रस्तुत नहीं कर सकती तो उस ड्यूटी क्रेडिट पर स्क्रिप जारी होने की तारीख से प्रति वर्ष 15 प्रतिशत ब्याज सहित उक्त रकम का भुगतान करना होगा । पार्टी के अप्रयुक्त/अंशतः अप्रयुक्त ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप वापस करने पर अप्रयुक्त/अंशतः अप्रयुक्त क्रेडिट को भुगतान की जाने वाली राशि से घटा दिया जाएगा।

10. उपर्युक्त शर्तों के अलावा पार्टी इस स्कीम के लिए सम्बद्ध सीमाशुल्क अधिसूचना द्वारा लगाई गई शर्तों का भी पालन करेगी ।

11. यह कि पार्टी निश्चित वचन देती है कि निर्यात आय वसूली की पूर्वोक्त शर्तों को पूरा न कर पाने की स्थिति में वह सरकार द्वारा अपेक्षित राशि के लिए एक बैंक गारंटी का निष्पादन करेगी ।

12. पार्टी सरकार से सहमत है कि पार्टी की सहमति के बिना तथा पार्टी की दायित्वों को किसी रूप में प्रभावित किए बिना सरकार को निम्नानुसार पूर्ण स्वतंत्रता होगी :

(क) कि स्क्रिप की किसी भी शर्त को बदल सकते हैं तथा समय-समय पर उक्त स्कीम को संशोधित कर सकते हैं ।

(ख) कि समय-समय पर उक्त पार्टी के निष्पादन का समय बढ़ सकता है तथा किसी दूसरे समय तक स्थगित कर सकती है अथवा

(ग) उक्त पार्टी के मद्दे सरकार द्वारा समय-समय पर किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकती है । और स्क्रिप से संबंधित किसी भी शर्त से छूट ले सकती है अथवा लागू कर सकती है और पार्टी को इस प्रकार के किसी बदलाव अथवा सरकार के पक्ष में किसी छूट अथवा हटाने के लिए पार्टी को समय-विस्तार के कारणों की वजह से उत्तदायित्व से

मुक्त नहीं किया जाएगा ।

इसके साक्ष्य स्वरूप पार्टी ने आज दिन—वर्ष— को इस करार को निष्पादित किया और पार्टी ने निम्नलिखित की उपस्थिति, में इस पर हस्ताक्षर किए, मुहर लगाई और सुपुर्द किया :-

(हस्ताक्षर) _____

(आवासीय पते सहित पार्टी का पूर्ण और विस्तृत विवरण)

साक्षी :

(हस्ताक्षर) _____

1. नाम _____

आवासीय _____

पता _____

2. नाम _____

आवासीय _____

पता _____

(इसे प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट/नोटरी पब्लिक द्वारा अधिप्रमाणन/प्रतिज्ञान कराना होगा)

इसे भारत के राष्ट्रपति की ओर से मैंने स्वीकृत किया है ।

()

सहायक महानिदेशक विदेश व्यापार/विदेश व्यापार विकास अधिकारी

टिप्पणी : 1. बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता प्रक्रिया पुस्तक के पैराग्राफ 2.20 के अनुसार होगी ।

2. * विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 के तहत डीईपीबी/अध्याय 3 के तहत विशिष्ट हस्तांतरणीय प्रोत्साहन स्कीम ।

3. आवेदन भरने के समय बैंक वसूली प्रमाण पत्र अथवा निर्यात आय (प्रयोजन के लिए यथा विनिर्दिष्ट) की वसूली के साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत किए बिना विदेश व्यापार नीति के अध्याय 4 के तहत डीईपीबी/विदेश व्यापार नीति के अध्याय-3 के तहत विशिष्ट हस्तांतरणीय प्रोत्साहन स्कीम के भरे जाने वाले आवेदन के लिए विधिक वचनबद्धता की आवश्यकता होगी ।

4. ** “ निर्यात की तारीख (अनुमत निर्यात आदेश की तारीख) से 24 महीने की समयावधि तक विधिक वचनबद्धता वैध होगी । डीईपीबी अथवा विदेश व्यापार नीति के अध्याय - 3 के तहत किसी विशिष्ट मुक्त रूप से हस्तांतरणीय प्रोत्साहन स्कीम के लिए आवेदन के मद्दे प्रस्तुत एस/बी की संख्या के मामले में, 24 माह की समयावधि नवीनतम एस/बी के अनुमत निर्यात आदेश तारीख से होगी ।”

बैंक गारंटी/विधिक करार निष्पादित करने के संबंध में दिशा निर्देश संबंधी टिप्पणी

1. बैंक गारंटी/विधिक करार आयातक/निर्यातक (पार्टी) और जमानती बैंक (प्रत्याभूतिदाता) द्वारा 15/- रुपए के न्यूनतम मूल्य के अथवा उस राशि के जो भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 या राज्य के अधिनियम जैसा भी मामला हो, के अन्तर्गत संबंधित राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाए, के गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर पर निष्पादित और हस्ताक्षरित किए जाएंगे ।

2. बैंक गारंटी/विधिक करार अथवा अन्तर्गत निष्पादित कोई अन्य दस्तावेज पर देय स्टाम्प शुल्क को पार्टी द्वारा वहन करना होगा ।

3. यदि पार्टी एकमात्र स्वामित्व वाली फर्म है तो बांड/विधिक करार उसके एक मात्र स्वामी द्वारा स्थायी और पूर्ण निवासीय पते सहित निष्पादित किया जाएगा ।

“ऐसे मामले में “विधिक करार के शुरू के पैराग्राफ में प्रयुक्त अभिव्यक्ति आयातक/निर्यातक” या “पार्टी” में उसके वारिस, उत्तराधिकारी, प्रशासक, समनुदेशी शामिल होंगे ।”

4. यदि पार्टी एक साझेदारी फर्म है तो बैंक गारंटी/विधिक करार भागीदार प्रबन्धक भागीदार के पते और उस स्थान के साथ जहाँ भागीदार फर्म का पंजीकृत कार्यालय स्थित है, उल्लिखित किए जाने वाले भागीदारों, या यदि भागीदारी विलेख में उल्लेख है तो प्रबन्धक भागीदार के माध्यम से भागीदार फर्म के नाम से निष्पादित किया जाएगा ।

“ऐसे मामले में विधिक करार के प्रारंभिक पैराग्राफ में प्रयुक्त “आयातक/निर्यातक” या “पार्टी” की अभिव्यक्ति में संबंधित कानूनी वारिस, उत्तराधिकारी, प्रशासक और प्रतिनिधि और संयुक्त रूप से तथा पृथक रूप से सभी साझेदार शामिल होने चाहिए तथा वे अंश शामिल होना चाहिए जहाँ उक्त फर्म के कार्यों पर निगमित निकाय का नियंत्रण नहीं है।”

5. यदि पार्टी एक लिमिटेड कम्पनी है, तो बैंक गारंटी/विधिक करार कम्पनी की मोहर के साथ और कम्पनी के पंजीकृत कार्यालय के पते का भी उल्लेख करते हुए, प्रबंध निदेशक या कम्पनी के दो निदेशकों द्वारा निष्पादित किया जाएगा इसी प्रकार बैंक गारंटी/विधिक करार कम्पनी की मुहर के साथ और कम्पनी के पते का भी उल्लेख करते

हुए, इस प्रयोजन के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा प्राधिकृत महा-प्रबंधक के बैंक के कम्पनी के वरिष्ठ कार्यकारी द्वारा इसे निष्पादित किया जाएगा। ऐसे मामलों में बैंक गारंटी/विधिक करार कम्पनी सचिव द्वारा प्रति हस्ताक्षरित होना चाहिए।

“उस मामले में, विधिक करार के प्रारंभिक पैराग्राफ में प्रयुक्त अभिव्यक्ति “आयातक/निर्यातक” या “पार्टी” में व्यापार में इसका उत्तराधिकारी और प्रतिनिधि शामिल होगा।

6. बंध पत्र/विधिक करार के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करने होंगे।

7. सामान्यतः बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता की अनुमत निर्यात आदेश की तिथि से कम से कम 24 महीने की वैधता रहेगी। यदि विदेश व्यापार नीति के अध्याय 3 के तहत डीईपीबी या किसी विशेष मुक्त रूप से हस्तांतरणीय प्रोत्साहन स्कीमों के लिए एक आवेदन के मद्दे कई एस/बी एस दायर किए जाते हैं तो नई एस/बी एस की तिथि अनुमत निर्यात आदेश से 24 महीने होगी।

8. यदि निर्यात आय प्राप्ति के लिए समयावधि में वृद्धि की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक या प्राधिकारी डीलर द्वारा दी जाती है, तो निर्यातक तदनुसार बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता की वैधता अवधि में वृद्धि कराएगा और भारतीय रिजर्व बैंक या प्राधिकृत डीलर द्वारा अनुमत विस्तार के प्रमाण के साथ संबंधित प्राधिकारी के पास उसकी मूल प्रति जमा करवाएगा।

9. आवेदक के पास प्रत्येक आवेदन या रिवोल्विंग बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता के मद्दे बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता दायर करने का विकल्प रहेगा। ऐसी रिवोल्विंग बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता इस उद्देश्य के लिए जारी दिशा-निर्देशों में यथा निर्दिष्ट कम से कम अवधि के लिए वैध होगी। इसके अलावा, रिवोल्विंग बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता एक विशिष्ट स्कीम के तहत सीमित रहेगी, जिसका तात्पर्य है कि उपरोक्त निर्धारित दिशा-निर्देशों के तहत एक निर्यातक/पार्टी के लिए अलग-अलग स्कीमों के लिए आवेदन दायर करने के लिए प्रत्येक स्कीम के लिए अलग बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता दायर करने की आवश्यकता होगी। एक क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास दायर की गई बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता का उपयोग अलग-अलग आवेदनों के लिए अलग क्षेत्रीय प्राधिकारी के पास दायर की जाने वाली बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता के लिए नहीं की जा सकेगी।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 30th March, 2009

No. 167 (RE-2008)/2004—2009

F. No. 01/94/180/982/AM09/PC 4.—In exercise of powers conferred under Para 2.4 of the Foreign Trade Policy, 2004—09, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendments in the Handbook of Procedures (Vol. 1) (RE-2008) :

1. At the end of Paragraph 2.20, a new paragraph 2.20A related to “*Execution of Bank Guarantee/Legal Undertaking for DEPB/Freely transferable Incentive Schemes under Chapter 3*” as mentioned below, shall be added:

<i>Execution of Bank Guarantee/Legal Undertaking for DEPB/Freely transferable schemes under Chapter 3</i>	<i>2.20 A</i>	<i>At the time of filing application for scrip(s) under DEPB Scheme/Freely transferable incentive Scheme under Chapter 3 of FTP without Bank Realisation Certificate (BRC), the applicant shall execute BG/LUT (as per Customs circular no. 58/2004) with the RA as per Appendix 25C or Appendix 25D respectively.</i>
--	----------------------	---

2. Two new Appendices i.e. Appendix 25C and Appendix 25D related to “*Execution of Bank Guarantee and Legal Undertaking for DEPB/Freely transferable Incentive Schemes under Chapter 3*”, as Appended to this Public Notice stands added in Handbook of Procedures, Vol.1 (Appendices and Aayat Niryat Forms).

3. Last sentence of Paragraph 3.23.13 clause (i) notified vide Public Notice No. 151 dated 26.2.2009 shall be substituted by the following:

“In case there is no pending claim and there is no cash deposit towards the amount immediately after the expiry of 12 months time period from the date of issuance of the Scrip, the RA shall initiate necessary action. If the Scrip holder does not pay the amount within 60 days of the expiry of aforesaid 12 months time period, the scrip holder shall be required to pay the said amount along with 15% interest per annum from the date of issuance of the Scrip(s) for the Duty Credit for which BRC or Documentary evidence (evidencing realisation of export proceeds as required under FTP or the Procedure laid thereunder) could not be produced. In case the Scrip holder surrenders the unutilized / partially unutilized Duty Credit Scrip, then unutilized / partially unutilized credit shall be deduced from the payable amount.

3. Paragraph 4.45, as amended vide Public Notice No. 151 dated 26.2.2009 stands substituted as follows:

“RA shall monitor all such cases wherein the Scrip(s) has been issued without Bank Realisation Certificate(BRC) and ensure that the BRC is submitted within 12 months from the date of issuance of the Scrip. In case no RBI extension is produced, RA shall initiate action for recovery of the same. In such cases, DEPB holder (the original applicant) shall deposit in cash or through debit of the valid DEPB / adjustment of pending DEPB claim for an amount equivalent to the Duty Free Credit allowed. If amount realized in Free Foreign Exchange is less, then payable amount would be reduced proportionately. However, if the DEPB holder does not pay the amount within 60 days of the expiry of the 12 months time period from the date of issue of the Scrip, he shall be required to pay the said amount along with 15% interest per annum from the date of issuance of Scrip(s) for the Duty Credit for which BRC or Documentary evidence (evidencing realisation of export proceeds as required under FTP or the Procedure laid thereunder) could not be produced by the DEPB holder. In case he surrenders the unutilized / partially unutilized Duty Credit Scrip, then unutilized / partially unutilized Credit shall be deducted from the payable amount.

In case of Cash Payment, the same shall be deposited in the Head of Account of Customs as stated in paragraph 4.29 above.”

This issues in public interest.

R. S. GUJRAL, Director General of Foreign Trade and ex-officio Addl. Secy.

APPENDIX 25C

BANK GUARANTEE FORMAT FOR DEPB SCHEME AND FREELY TRANSFERABLE INCENTIVE SCHEMES OF CHAPTER 3

To,
The President of India
Acting through the Director General of Foreign Trade

In consideration of the President of India, acting through the Director General of Foreign Trade (which expression shall be deemed to include the Joint Director General of Foreign Trade/Deputy Director General of Foreign Trade, or any other authority for the time being authorised to perform the duties of Joint Director General of Foreign Trade/Deputy Director General of Foreign Trade), Ministry of Commerce, Government of India, New Delhi (hereinafter referred to as the Government) having notified the _____ Scheme* (fill up the actual specific

Scheme) in the Foreign Trade Policy, 2004-09, as amended from time to time (herein after referred to as "Scheme"). The importer/exporter _____ (full expanded name of the importer/exporter with complete address and IEC No.) (herein after referred to as 'party', which expression shall be deemed to include his/her heirs, successors, administrators and assignee, if the firm is Sole Proprietary firm/jointly and severally all the Partners through their legal heirs, successors, administrators, and assignee as well as the portions where body corporate or, not having the control of the affairs of the said firm, if it is Partnership firm/successors in business and assignee, if firm is limited company) desires to apply for scrip(s) under the Scheme (herein after referred to as scrip(s) for import of the goods allowed under the Scheme) on fulfilling the terms and conditions of the Scheme, which inter-alia stipulates production of a Bank Guarantee in case the party applies for the scrip(s) without submission of the Bank Realisation Certificate or other documents evidencing realisation of export proceeds (as per terms and conditions of the Scheme). We _____ (indicate the name and full address and other particulars of the Bank) (hereinafter referred to as Bank) at the request of the party do hereby unconditionally and irrevocably undertake to pay the Government an amount not exceeding Rs. _____ against any loss or damage caused to or suffered by the Government by reason of any failure on the part of the said party to furnish the Bank Realisation Certificate or other documents evidencing realisation of export proceeds (as per the terms and condition of the Scheme) within the time period endorsed in the Scrip(s).

2. We _____ (indicate the name of Bank) do hereby undertake to pay the amounts due and payable under this guarantee without any demur or protest, merely on a demand from the Government stating that the amount claimed is due on account of non-realisation of export proceeds or any loss suffered by the Government by reason of breach by the party of any of the terms or conditions of the said Scheme. Any such demand made on the Bank shall be conclusive as regards the amount due and payable by the Bank under these presents.

3. We undertake to pay to the Government any money so demanded, notwithstanding any dispute or disputes raised by the party in any suit or proceeding pending before any court or Tribunal relating thereto and our liability under these presents is absolute and unequivocal.

4. We, _____ (indicate the name of Bank) further agree that the guarantee herein contained shall remain in full force and effect during the period that would be taken for the performance of the scrip(s) and that it shall continue to be enforceable till all the obligations of the party under or by virtue of the scrip(s) have been fully discharged to the satisfaction of the Government or till Jt.DGFT/Dy.DGFT, or any Regional Authority for the time being authorised to

perform the duties of Jt.DGFT/Dy.DGFT, Ministry of Commerce, New Delhi certifies that the terms and conditions of the scrip(s) have been fully and properly carried out by the party and accordingly discharges this guarantee. Provided, however, unless a demand or claim under this guarantee is made on us in writing on or before the _____ **, we shall be discharged from all liability under this guarantee thereafter.

5. We _____ (indicate the name of bank), further agree with the Government that the Government shall have the fullest liberty without our consent and without affecting in any manner our obligations hereunder (i) to vary any of the terms and conditions of the scrip(s) and modify the said scheme from time to time or (ii) to extend time of performance by the said party from time to time or to postpone for any time or (iii) from time to time any of the powers exercisable by the Government against the said party and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the scrip(s) and we shall not be relieved from our liability by reason of any such variation, or extension being granted to the said party, or for any forbearance, act or omission on the part of the Government, or any indulgence by the Government to the scrip holder, or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to sureties would, but for this provision, have effect of so relieving us.

That this shall be a continuing Bank Guarantee and shall not be discharged by any change in the constitution of the party or of the Bank.

That the guarantor shall not revoke the guarantee without prior written consent of the Government.

"Dated 1 the _____ day of _____ year _____ for _____
_____ indicate the name of the Bank)"

Note: 1. BG/LUT shall be as per paragraph 2.20 of HBP v.1.

2. * DEPB under Chapter 4/Specific Transferable Incentive Scheme under Chapter 3 of FTP.

3. ** The Bank Guarantee shall be valid till the expiry of the time period of 24 months from the date of export (Let Export Order Date). In case of a number of S/Bs filed against one application under DEPB Scheme / Incentive Scheme, 24 months time period shall be from the LEO date of latest S/Bs.

1250 GI/09-5

APPENDIX 25D**LEGAL AGREEMENT / UNDERTAKING FORMAT FOR DEPB SCHEME AND FREELY TRANSFERABLE INCENTIVE SCHEMES OF CHAPTER 3**

To

The President of India

Acting through the Director General of Foreign Trade (which expression shall be deemed to include the Joint Director General of Foreign Trade/Deputy Director General of Foreign Trade/Asst. Director General of Foreign Trade), Ministry of Commerce, Udyog Bhavan, New Delhi - 110 011.

This DEED of Agreement made on _____ day of _____ month ____ year BETWEEN _____ (full expanded name of the Importer/Exporter with complete address and IEC Code No.) hereinafter referred to as the 'party', which expression shall be deemed to include his/her heirs, successors, administrators and assignee, if the firm is Sole Proprietary firm/jointly and severally all the Partners through their legal heirs, successors, administrators, and assignee as well as the portions where body corporate or not having the control of the affairs of the said firm, if it is Partnership firm/successors in business and assignee, if firm is limited company.

AND

The President of India (hereinafter referred to as 'the Government' which expression shall include his successors in office and assigns).

WHEREAS the party desires to apply for scrip(s) (herein after referred to as scrip(s) for import of goods allowed under the Scheme) on fulfilling the terms and condition of the Scheme, which inter-alia stipulates production of a Legal Undertaking (herein after referred to as 'LUT') in case the party applies for the scrip(s) without submission of the Bank Realisation Certificate or other documents evidencing realisation of export proceeds as required under the _____ Scheme (Fill up the actual specific Scheme*) (herein after referred to as 'Scheme') notified by the Government under the Foreign Trade Policy, 2004-09, as amended from time to time, with an obligation to realize the export proceeds (FOB value of exports based on which duty credit shall be allowed under the Scheme) within the time period endorsed on the scrip(s).

AND WHEREAS the Government may grant a Scrip(s) to the party for the full value applied for or for a lesser value, as it may be deemed fit and as per the terms and conditions of the Scheme.

AND WHEREAS one of the terms of the Scrip(s), which may be issued as above, is that the party is to enter into an agreement/undertaking with the Government on the terms and conditions appearing hereinafter.

AND WHEREAS the party do hereby unconditionally and irrevocably undertake to pay the Government an amount not exceeding Rs. _____ which is due and payable under this agreement without any demur or protest, merely on a demand from the Government stating that the amount claimed is due on account of non-realisation of export proceeds or any loss suffered by the Government by reason of breach by the party of any terms or conditions of the said Scheme.

AND WHEREAS the party has to furnish a Legal Agreement in anticipation of the Government issuing Scrip(s) as above, based on the obligation to realize the export proceeds against exports, based on which duty credit is to be allowed under the Scheme.

AND WHEREAS the party has agreed to realize the export proceeds to the extent of FOB value to be shown in the scrip(s) or as may be endorsed by the Government in the Scrip(s), within the time period as required under the scrip(s), which may be issued.

AND WHEREAS the party has agreed:

- a) to fulfill all the conditions of _____ Scheme (indicate the name of the scheme) under which the Scrip(s) may be issued;
- b) to fulfill all the terms and conditions of the Scrip(s) which may be issued;
- c) to fulfill the conditions subject to which the goods may be cleared for imports by the Customs authorities including conditions imposed under the relevant Customs notification pertaining to the Scheme;
- d) to send a 'Statement of export proceeds realisation' shipping bill wise, to the Regional Authority concerned, in original every 3 months beginning from the date of issuance of individual scrip;
- e) to furnish from a Nationalised / Scheduled bank, in original, a Bank Realisation Certificate (BRC) for the FOB value based on which the scrip(s) to be issued and such other documents as may be demanded by the Regional authorities as evidence for the realisation of export proceeds made;
- f) that in the event of his default in meeting the aforesaid obligations / conditions, he shall immediately pay an amount equal to the duty credit issued. If the party does not pay the amount within 60 days of the expiry of 12 months time period from the date of issue of the scrip, the party shall be required to pay the said amount alongwith 15% interest per annum from the date of issuance of Scrip(s) for the duty credit for which BRC or Documentary evidence (evidencing realisation of export proceeds), as required under FTP or Procedure laid thereunder, could not be produced by the party. In case the party surrenders the unutilized / partially unutilized Duty Credit Scrip, then unutilized / partially unutilized credit shall be deducted from the payable amount.

g) that the Government may modify the Scheme from time to time.

NOW, THEREFORE THE CONDITIONS OF THE AGREEMENT ARE AS FOLLOWS:

In anticipation of granting the said Scrip(s) by the Government as aforesaid, the party hereby declare(s) and agree(s):

(i) That the party shall comply with all the obligations under the aforesaid Scheme specified by the Government and the conditions specified in the Scrip(s) to be issued for import and other conditions specified herein above.

(ii) That if the party fails to realise the whole or part of the export proceeds under the Scheme, including the terms and conditions stipulated in the Scrip(s) or fails to furnish any information required under the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, or the Orders made thereunder or the Rules framed thereunder, on the written demand made by the Government of the amount, in whole or part, the party shall forthwith without any demur or protest, pay to the Government the sum demanded.

(iii) That notwithstanding any right Government may have directly against the party in any form, and notwithstanding any dispute raised by the party in any form, the Government's written demand to the party shall be final and binding.

(iv) That this Agreement shall continue and shall not be discharged by any change in the constitution of the party.

(v) The party undertakes to pay simultaneously a sum equivalent to the duty credit issued by way of liquidated damages to the Government. The decision of the Government shall be final and binding on the party.

(vi) That this Agreement is executed by the party in public interest.

(vii) That the payment of the amount demanded by the government under this Agreement shall not affect the liability of the party to any other action, including the initiation of legal proceedings for confiscation of the imported material and refusal of further Scrip(s) / Authorisation(s), and all other liabilities, penalties and consequences under the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, and the Orders and Rules made thereunder, that may be decided by the Government.

(viii) That this Agreement shall remain in full force until all the obligations of the party are fulfilled to the full and final satisfaction of the Government as specified above and till such satisfaction is communicated to the party.

(ix) That the party unconditionally and irrevocably undertakes that in the event of his default in meeting the aforesaid obligation of furnishing the Bank Realisation Certificate evidencing realisation of export proceeds within 12 months time period from the date of issue of the Scrip(s), they shall immediately pay an amount equal to the duty credit issued. If the party does not pay the amount within 60 days of the expiry of 12 months time period from the date of issue of the scrip, the party shall be required to pay the said amount alongwith 15% interest per annum from the date of issuance of Scrip(s) for the duty credit for which BRC or Documentary evidence (evidencing realisation of export proceeds), as required under FTP or Procedure laid thereunder, could not be produced by the party. In case the party surrenders the unutilized / partially unutilized Duty Credit Scrip, then unutilized / partially unutilized credit shall be deducted from the payable amount.

(x) That the party shall also abide by the conditions imposed by the relevant Customs notification for the Scheme in addition to the aforesaid conditions.

(xi) That the party unconditionally and irrevocably undertakes that in the event of his default in meeting the aforesaid condition of export proceeds realisation, they shall execute a Bank Guarantee for an amount as required by the Government.

(xii) The party further agrees with the Government that the Government shall have the fullest liberty without any consent of the party and without effecting in any manner the obligations of the party hereunder: (a) to vary any of the terms and conditions of the scrip(s) and modify the said scheme from time to time or (b) to extend time of performance by the said party from time to time or to postpone for any time or (c) from time to time any of the powers exercisable by the Government against the said party and to forbear or enforce any of the terms and conditions relating to the scrip(s) and the party shall not be relieved from the said liability by reason of any such variation, or extension being granted to the party for any forbearance, act or omission on the part of the Government or any indulgence by the Government to the scrip holder or by any such matter or thing whatsoever which under the law relating to Legal Undertaking would, but for this provision, have effect of so relieving the party.

IN WITNESS WHEREOF the party hereto has duly executed this Agreement on this ____ day of ____ month ____ year ____ signed, sealed and delivered by the party in the presence of:

(Signature)_____

(full and expanded description of the party with residential address)

Witness: _____

(Signature)

1. Name _____

Residential _____

Address _____

2. Name _____

Residential _____

Address _____

(To be authenticated/affirmed by 1st Class Magistrate/Notary Public)

Accepted by me on behalf of the President of India.

(_____)

Asstt. DGFT/ Foreign Trade Development Officer

Note: 1. Bank Guarantee (BG) / Legal Undertaking (LUT) shall be as per paragraph 2.20 of HBP v.1.

2. * DEPB under Chapter 4/Specific Transferable Incentive Scheme under Chapter 3 of FTP.

3. LUT is required for the application(s) to be filed for DEPB under Chapter 4 of FTP/Specific Transferable Incentive Scheme under Chapter 3 of FTP without furnishing the Bank Realisation Certificate or the documents evidencing realisation of export proceeds (as prescribed for the purpose) at the time of filing application.

4. ** "The LUT shall be valid for a time period of 24 months from the date of export (Let Export Order Date). In case of a number of S/Bs filed against one application either for DEPB or for any specific freely transferable Incentive Schemes under Chapter 3 of FTP, 24 months time period shall be from the LEO date of latest S/Bs."

NOTE FOR GUIDANCE IN THE MATTER OF EXECUTING BANK GUARANTEE (BG) / LEGAL AGREEMENT(LUT)

1. The Bank Guarantee /Legal Agreement is to be executed and signed by the importer/exporter (party) and the surety Bank (Guarantor) on a non-judicial stamp paper of the minimum value of Rs. 15/-, or any amount as may be prescribed by the concerned State Government under the Indian Stamp Act, 1899 or State Act, as the case may be.

2. Any stamp duty payable on the B.G./LUT or any document executed thereunder shall be borne by the party.

3. If the party is a sole proprietary firm, the Bond/Legal Agreement shall be executed by the Sole Proprietor of the firm, along with his permanent and complete residential address.

"In such a case, the expression "Importer/Exporter" or "Party" used in the opening paragraph of the Legal Agreement should include his/her heirs, successors, administrators and assignee".

4. If the party is a partnership firm, the B.G./LUT shall be executed in the name of the partnership firm, through the partners to be specified, or the Managing partner, if so specified in the Partnership Deed, along with the address of the partner/Managing Partner, and the place where the Registered Office of the partnership firm is situated.

"In that case, the expression "Importer/Exporter" or "Party" used in the opening paragraph of the Legal Agreement should include jointly and severally all the partners, through respective legal heirs, successors, administrators and assignee as well as the portions where body corporate or not having the control of the affairs of the said Firm".

5. If the party is a Limited Company, the B.G./ LUT shall be executed by the Managing Director or two Directors of the Company, along with the seal of the Company and also specifying the address of the Registered Office of the Company.

Alternatively the B.G./ LUT shall be executed by a senior executive of the Company of the rank of General Manager and one of the Directors of the Company who have been authorised by the board of Directors for this purpose, along with the seal of the Company and also specifying the address of the Company. In such cases B.G./ LUT shall be countersigned by the Company Secretary.

"In that case, the expression "Importer/Exporter" or "Party" used in opening paragraph of the Legal Agreement should include its successors in business and assignee".

6. Each page of the Bond / Legal Agreement is to be signed.

7. Normally the BG / LUT shall have a validity of at least 24 months from the date of LEO. In case a number of S/Bs are filed against one application either for DEPB or for any specific freely transferable Incentive Schemes under Chapter 3 of FTP, 24 months time period shall be from the LEO date of latest S/Bs.

8. In case, extension in time period for export proceeds realisation is allowed by RBI or Authorized Dealers, the exporter shall get the validity of BG / LUT extended accordingly and the original copy of the same shall be submitted to the RA concerned along with the evidence of extension allowed by RBI or the Authorized Dealer.
9. Applicant shall have the option to file BG/ LUT against each application or *a Revolving BG / LUT*. Such a revolving BG / LUT shall be valid at least for a period as stated in the guidelines issued for the purpose. Further the revolving BG/LUT shall be limited to a specific scheme, which means that for an exporter/party filing application for different schemes under the aforesaid laid down guidelines, shall be required to file separate BG/LUT for each scheme. BG/LUT filed in one RA shall not be utilized for BG/LUT to be filed in another RA for different application.